

ईशान की बल्लेबाजी पर रोहित की प्रतिक्रिया कहा मैं उनका माइंडसेट जानता है

लखनऊ। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अपने पुराने रग में नज़ारा आए। ईशान भल ही इस मैच में शतक बनाने से चुक गए लेकिन उन्होंने केल 56 गेंदों पर 89 रन की गेंद खेल कर जीत की नीत रखी। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने 2 विकेट खोकर 199 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह ईशान की दूसरी अर्थशतकीय पारी थी। ईशान ने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। ईशान की यह पारी टी20 में भारतीय विकेटकीपर द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ रोहित शर्मा ने ईशान किशन की बल्लेबाजी की प्रशंसा की और कहा कि उम्में यायगता है और दूसरे छोर पर खेल होकर किसी बल्लेबाज द्वारा किशन ने लेकर देखना सुखद है। मैं ईशान को लंबे समय से जानता हूँ। मुझे उनकी माइंडसेट के बारे में पता है। मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूँ। बस उन्हें एक इस तरह के पारी को जरूरत थी जो उन्होंने इस मैच में खेला। जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी



बाट कर रहे थे। हालांकि मैच के बाद ईशान किशन ने कहा कि ओपनिंग स्ट्राउट को लेकर वे आश्वस्त नहीं हैं और अपनी भी क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए वे तैयार हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ भी ईशान को रोहित के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला था। लेकिन वे सफल नहीं हुए थे।

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जीत से किया आगाज, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई

नई दिल्ली। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने टीम के कप्तान दासुन शनाका ने टास



आउट कर दिया। टीम को दूसरा झटका तीसरे ओवर में लगा। भवनेश्वर ने कामिल मिशाया 13 रन पर पवेलियन भेजा। साथें ओवर में जनिथ लियानगो को आउट 11 रन पर आउट करके बैटेशन अव्यावर ने श्रीलंका को तीसरा झटका दिया। 10वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने दिनेश चाहौल को 10 रन पर आउट करके श्रीलंका को छाँथा झटका दिया। दासुन शनाका को तीन रन पर आउट करके यजुवेंद्र चहल ने टीम को पांचवां झटका दिया। चमिका करुणारत्ने 21 रन को बैटेशन अव्यावर ने पवेलियन भेजकर श्रीलंका को छाँथा झटका दिया। अलंकार 53 रन जबकि दुश्मन्या चमीरा 24 रन बनाकर नाबाद रहा। भारत की तरफ से भूमि व अव्यावर को दो-दो जबकि चहल और जडेजा को एक एक फलता मिली। रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अव्यावर, संजू सेमसन, दीपक हुड़ा, रवींद्र जडेजा और बैठकर करने के तीन रन पर आउट करके यजुवेंद्र चहल ने टीम को पांचवां झटका दिया। चमिका करुणारत्ने 21 रन को बैटेशन अव्यावर ने श्रीलंका को छाँथा झटका दिया। श्रेयस अव्यावर 57 और रवींद्र जडेजा 3 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में श्रीलंका का पहला विकेट पारी की पहली ही गेंद पर गिर गया। भवनेश्वर कुमार ने अपने बल्लेबाज पुष्यम निसानका को गोलंड डक पर

जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के तुकड़ान पर 199 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 200 रन का टारोर दिया। जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य के बावजूद पर्याप्त नहीं दासुन शनाका ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। ये टी20 में बैटोर फुलटाइम

IPL 2022: 26 मार्च से होगा आइपीएल के 15वें सीजन का आगाज, 29 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। आइपीएल गवर्नर ने बैठक में श्रीलंका की बैठक में ये फैसला लिया गया। ब्रिजेस पर्टेल की अग्रआई में हुई इस बैठक में श्रीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली

ने वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया क्योंकि वो इस वर्क लैंडन में है। गवर्नर ने बैठक में फैसला किया गया है कि सभी लीग मुकाबले मैंबी में आयोजित किया जाए। बैठक में फैसला किया गया है कि लेकिन उनकी जीत की गेंद पर खेला जाएगा। ब्रिजेस पर्टेल के शेंघूपूल की पूरी तरह से कुछ दिनों में फाइनल किया जाएगा। इनसाइड स्पॉर्ट्स के मूलाबिक फिलहाल आइपीएल को लेकर ये वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी

किया जाएगा। ब्रिजेस

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बोले दुनिया की सबसे बड़ी लीग कोई नहीं इसके आसपास

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम काफी लंबे समय बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग की खिलाड़ियों को दोनों फैंचाइजिंगों और कोलाकाता नाइटराइडर्स ने अपने अधिकारिक ट्रिप्टर अकाउंट से अपने स्ट्रक्चर और क्रिकेटर अकाउंट से अपने शक्तिशाल में शामिल आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को दौरे ले रहे। शुभकामनाएं दी थीं। मौताल है कि इस दौरे के कारण आइपीएल 2022 की शुरुआत में कर्फ़ आस्ट्रेलियाई नहीं होगी। इससे खुश होकर पाकिस्तान के पूर्व सिन्यर दानिश कनेरिया ने

ने आइपीएल 2022 की नीलामी में आइपीएल दूनिया की सबसे बड़ी लीग है। इससे बड़ा कुछ नहीं है और इसके आसपास भी कोई नहीं है। आइपीएल में जुड़े लोग क्रिकेट में सम्पादित लोगों में से हैं। हर बार जब कोई टीम पाकिस्तान छोड़ती है तो कुछ लोग भारत को जीत देते हैं। यदि कोई खिलाड़ी दौरे से बाहर हो जाता है तो दोष भारत पर आ जाता है। कुछ भी गलत होता है, किम्बार दूरी पर आ जाता है। लेकिन वहां से कोई रिएक्शन नहीं आता। आइपीएल को आपने खिलाड़ियों के अपने खिलाड़ियों के प्रति जो भाव दिखाया बहुत शानदार था।

लेखनऊ। भारत ने श्रीलंका को पहले टी20 मैच में 82 रनों से हरा दिया। इस मैच में दो मृणन बाट पारी कर रहे रवींद्र जडेजा के बल्लेबाजी के लिए ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन पहले मैच में उन्हें नंबर 7 नंबर पर रवींद्र जडेजा के लिए भेजा गया था। हालांकि जडेजा लंबी पारी नहीं खेल पाए और महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। मैच के बाद रोहित शर्मा ने इस फैसले के बारे में कहा। जडेजा को तारीफ की है। इसे दुनिया की दूसरी लीग उसके करीब भी नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं। वहां कुछ भी गलत नहीं है। भारत हमेशा अपने

कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'आइपीएल फैंचाइजिंगों को पाकिस्तान दौरे के लिए आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।' वहां कुछ भी गलत नहीं है। भारत हमेशा अपने

कोलाकाता नाइटराइडर्स के लिए ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन वहां से जो आपने खिलाड़ियों को आपने खिलाड़ियों के प्रति जो भाव दिखाया बहुत शानदार था।

लेखनऊ। भारत ने जारी किया वे लिए ऊपर बल्लेबाजी के लिए अपने गेंदबाज थे जिन्होंने 4 ओवर का गेंदबाजी के लिए ऊपर बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी में जीडेजा ने 28 रन देकर विकेट लिया। रोहित जडेजा का पहले ही एक मल्टी युट्यूलियाई खिलाड़ी बना चुक है। टीम के 15वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। 29 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बार 10 दिन में खेलेंगे।

सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया।

मैत्रजन टीम ने 62 रनों से जीत हासिल की। सबसे छोटे कार्फैट में टीम इंडिया का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी संकेतन दिया गया।

मैत्रजन टीम का विजयी संकेतन दिया गया। इसके बाद एक टीम का विजयी सं

सम्पादकीय

वन्या स्वरूप-काले जों में
लड़कियों का हिजाब पहनना
इतना अहम मुद्दा है कि वह
राष्ट्रीय विवाद और वैश्विक
ध्यानाकर्षण का केंद्र बन जाए

अतीत से लेकर वर्तमान तक इस्लामिक जगत में हिजाब पहनना कभी अनिवार्य नहीं रहा। सऊदी अरब सहित अरब के खाड़ी देशों में महिलाएं पहले से ही हिजाब के साथ-साथ अमूमन बुर्का भी पहनती आई है। अफगानस्तान में तो वे महिलाएं भी पारपरिक रूप से हिजाब पहनती आई हैं, जो भले ही बुर्का न पहनती हों। हालांकि तुर्की जैसे कुछ देशों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। यह परपरा महान तुर्क नेता कमाल अताउर्क द्वारा 1928 में तुर्की को पंथीनरपेक्षण गणतंत्र घोषित करने के साथ आरंभ हुई। मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप टैयप एर्दोगन के राज में तुर्की आधिकारिक रूप से तो पंथीनरपेक्षण राष्ट्र बना हुआ है, लेकिन वहां धार्मिक कठुरता बढ़ी है और इसी कड़ी में हिजाब से प्रतिबंध हटा लिया गया है। यहां तक कि एरीगन की पत्नी भी हिजाब पहनती है। पिछली सदी के छठे दशक से मिस में हिजाब पहनने वाली बहुत कम महिलाएं दिखती थीं। जब 1977-78 के दौरान मैं काहिरा में था तब स्कूल-कालेज जाने वाली ऐसी लड़कियां कम ही दिखती थीं, जिन्होंने हिजाब पहना हो। हालांकि 1979 में ईरान में आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हुई इस्लामिक क्रांति और सऊदी अरब द्वारा कठुर बहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने की कवायद ने मुस्लिम जगत में रुद्धिविद्वान बढ़ाने का काम किया, जिसमें महिलाओं का पहनावा भी शामिल है। इसी कारण पिछले चार दशकों से कई इस्लामिक देशों में हिजाब का चलन आम हुआ है। जो महिलाएं पहले हिजाब नहीं पहनती थीं, वे भी अब इसे पहनने लगीं। इसे इस्लामिक पहचान से जोड़ दिया गया। 1990-93 के दौरान अपने मलेशियाई प्रवास के दौरान कुआलालंपुर में एक स्थानीय मित्र ने मुझे बताया कि उनके देश में उन स्थानों में भी इसे अपना लिया गया, जहां इसका आम चलन नहीं था। स्पष्ट है कि समकालीन दौर में हिजाब धीरे-धीरे इस्लामिक पहचान का हिस्सा बनता गया। यही कारण है कि कर्नाटक के हालिया हिजाब विवाद को लेकर इस्लामिक जगत में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां सामने आईं। इसने पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का अवसर दे दिया। तीन तलक के मामले में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं मिली थी, क्योंकि ऐसी कुप्रथा पर कई मुस्लिम देशों में ही प्रतिबंधित हैं और तमाम ने तो उस पर रोक के लिए बाकायदा कानून भी बनाए हैं। ऐसे में तीन तलक की समाप्ति के पक्ष में जो तर्क दिए गए, वे कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध के लिए नहीं दिए जा सकते। हिजाब विवाद पर अब अदालत में सुनवाई हो रही है। अदालत इस पर कानूनी रवैया अपनाएगी, परंतु विधिक निण्य सभी सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में संभव नहीं होते। विशेषकर उन मुद्दों का जो समाज के विभिन्न गर्गों की सामाजिक पहचान से संबंधित हों। ऐसी पहचानें भाषा, खानपान, पहनावा और जीवन के कई अन्य पहलुओं के आधार पर परिभाषित होती हैं। समय के साथ ये परिवर्तित हो जाती हैं, किंतु ऐसे बदलाव थोपे नहीं जा सकते। यदि इसके लिए दबाव बनाया जाएगा तो प्रतिरोध स्वाभाविक होगा। ऐसा प्रतिरोध सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है और राजनीतिक गतिविधियों में यह झलकने भी लगा है। इसीलिए भारत जैसे व्यापक विविधता वाले देशों में राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे संयम और सरकृता के साथ काम करें ताकि उदार नीतियां सुनिश्चित की जा सकें। इसके लिए बहुत बुद्धिमानी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह तय किया है कि विकास का लाभ समाज के सभी गर्गों तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया है। इसी क्रम में सबका विश्वास हासिल करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक समुदाय इसे लेकर आश्वस्त हो कि उसकी पहचान को भी समान मिले। सामाजिक शांति, सद्व्यवहार और स्थायित्व कायम रखने का यही तरीका है। किसी भी देश को प्रगति और विश्व में ऊंचा कद हासिल करने के लिए सामाजिक स्थायित्व अपरिहार्य है सामाजिक रूप से विभाजित और छंडित देश बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता।



विसैन्यीकरण की चाल की आशंका शायद किसी को नहीं थी। रूस यूक्रेन के हवाईअड़ों और बंदरगाहों को इसलिए निशाना बना रहा, ताकि उसकी मदद के लिए बाहर से रसद न आ सके। राजधानी कीब और हथियाए गए पूर्वी डानबास प्रांत के बीच का संपर्क तोड़? की कोशिश भी हो रही है। बेलारूस की राजधानी मिस्क में 2014-15 में हुए जिस युद्धविराममें समझौते का पालन करने का पुतिन बार-बार जिक करते रहे, उसे उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। अब वह यूक्रेन की कमर तोड़कर वहां बेलारूस जैसी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को लेनिन ने बनाया था और वह हमेशा से रूस का

एक टुकड़ी वहां तैनात है। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों के बावजूद पुतिन ने वहां से सेना नहीं हटाई। इस तरह रूस ने यूक्रेन को अब चारों दिशाओं से घेर रखा है। इसलिए नाटो के सुरक्षा कर्व के बिना यूक्रेन का स्वतंत्र और स्थिर रह पाना अब कठिन लगता है। यूक्रेन में 15 परमाणु संयंत्र हैं, सबसे बड़ा जैफरीजिया प्रांत में है, जिसकी सीमा पूर्वी डोनेस्क प्रांत से लगती है। यदि यह परमाणु संयंत्र बमबारी की चपेट में आया तो ढेरीबिल जैसी दुर्घटना भी हो सकती है, जो समूचे पूर्वी यूरोप के लिए एक भीषण त्रासदी साबित होगी। नाटो देश अभी केवल रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े करने की बातें ही कर रहे हैं, पर रूसी

न्यूजलं बिंदु पर पहुंच गई है। इससे महागाई बढ़गी और हो सकता है कि रूस के कुछ बैंक दिवालिया हो जाएं। अमेरिका और यूरोप ने अपने वित्त और कर्ज बाजारों को रूस के लिए बंद करने के कदम उठाए हैं। जर्मनी ने रूस की नई गैस पाइपलाइन को चालू करने की अनुमति न देने का एलान किया है, पर रूस के तेल और गैस निर्यात पर पांदी की बात नहीं की जा रही है। रूस तीसरा सबसे बड़ा तेल और दूसरा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। यूरोप की 40 प्रतिशत गैस रूस से आती है। जर्मनी, इटली और स्वर्यं यूक्रेन गैस के लिए रूस पर निर्भर है। बिना प्रतिबंधों के ही तेल की कीमतें सौ डालर पार कर चुकी हैं और गैस के दाम तिगुने हो

श निर्माण के साथ आगे प्रदेश की अर्थव्यवस्था

किसी भी राज्य की प्रगति इस तथ्य पर आधारित होती है कि राज्य के पास कितनी पोर्टेशियल (यानी राज्य के पास कितनी प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संपदा) है और लीडरशिप का विजन व उसकी प्रबंधन क्षमता कितनी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2017 से ठीक पहले के लगभग तीन दशकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के वितरण में कुशलता, दक्षता और समयबद्ध पर्याम देने की प्रक्रिया के साथ-साथ पारदर्शिता की बेहद कमी रही। परिणाम यह हुआ कि इन दशकों में राज्य उत्तरात्तर गैर विकासवादी प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ा, फलत बुनियादी ढांचा और विकास नेपथ्य में चला गया, परंपरागत उद्यम मृतप्राय हुआ और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर बीमार हुआ, कृषि तकनीकी उन्न्यन से बचत हुई, बोरोजगारी और गरीबी बढ़ी जिससे सामाजिक संरचना में तमाम विभाजक रेखाएं खिंच गई। प्राकृतिक, भौतिक और मानव संपदा से संपन्न उत्तर प्रदेश बीमार राज्य की श्रेणी में पहुंच गया। वैश्वीकरण ने विकास का एक नया माडल दिया था जिसमें ट्रिक्ल डाउन विकास को नीचे तक पहुंचाने का सबसे बेहतर उपकरण करार दिया गया। लेकिन हुआ क्या 'बाटम आफ पिरामिड तक विकास तो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही अवशोषित कर लिया गया। फिर समरसता कहां से आती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'जैम (जनधन-आधार मोबाइल) माडल ने सरकार की सल्लिङडी की लीकेज को रोक दिया। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था ने सीधे उसे ही लाभ पहुंचाया जो इसका हकदार था। परिणामस्वरूप 'बाटम आफ पिरामिड नई शक्ति हासिल करने लगा। उत्तर प्रदेश इस व्यवस्था में देश के अंदर सबसे आगे रहा। स्वाभाविक है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में उन लोगों की संख्या कहीं ज्यादा होगी जो 'जैम ट्रिनिटी से लाभान्वित हैं। इसके माध्यम से राज्य में कराड़ों लोगों को अनेक प्रकार से लाभ मिला। बहुत से अध्ययन बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास प्रदेश के पास एक बड़ा बाजार है और कुशल मानव पूँजी है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा एवं संपर्क, कानून एवं व्यवस्था, निवेश आकर्षण तथा कारोबारी परिवेश के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए। इन आफ दूँग बिजेस उत्तर प्रदेश की रैकिंग का 14वें पायदान से दूसरे पायदान तक पहुंचना इसका प्रमाण है। इसी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के प्रति व्यवसायियों व निवेशकों की अवधारणा बढ़ली और यह प्रदेश बीमार से संभावनाओं की भूमि बना। दरअसल इसकी वास्तविक नींव मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट



पर रोजगार का सुजन व आय में वृद्धि निहित होती है। राज्य सरकार ने यदि दर्जनों अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा कर 22 लाख अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया उससे कृषकों को मुफ्त पानी मिला। यानी उसका ईंधन पर होने वाला व्यय बचा, उसका श्रम और समय बचा तथा समय पर सिंचाई के लिए मिले पर्याप्त पानी ने कृषि पर लागत कम करने के साथ-साथ किसान की आय में वृद्धि की। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा 15 करोड़ लोगों को महीने में दो बार राशन दिया गया। इसने परिवारों की भूख की चिंता को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही, यदि एक करोड़ वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को 12 हजार रुपये सालाना दिया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से यह उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च होता होगा। विभिन्न प्रकार

की सहायता योजनाओं के तहत प्रदेश के नागरिकों को दी गई सहायता राशि ने एक तरफ उनके जीवन को खुशहाल और चिंतामुक्त बनाने का काम किया तो दूसरी तरफ बाजार की मांग-आपूर्ति देने को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि जब कोरोना कालखंड में अन्य राज्यों में मांग और आपूर्ति देने लड़खड़ाई, उदयम बंद हुए और लोग बेरोजगार हुए, तब उत्तर प्रदेश सभी के बीच संतुलन साधते हुए तेजी से आगे बढ़ता रहा। पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत पीछे चला गया था। योगी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव एवं प्रयागराज में भव्य एवं दिव्य कुंभ का आयोजन कर उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक-आद्यात्मिक अर्थव्यवस्था की एक नई शुरुआत की। संस्कृति और अद्यात्म आधारित अर्थव्यवस्था आने वाले समय में लेवल अर्थव्यवस्था में ही मल्टीप्लायर की भूमिका नहीं निभाएगी, बल्कि इंज आफ लिविंग और हैपीनेस का मूलभूत आधार साबित होगी। इस दौरे से देखें तो पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के जिस माडल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐकसित किया है, उसमें अंत्योदय संबंधी दृष्टिकोण तो है ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आद्यात्मिक-सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था और हैपीनेस का मंत्र तथा 'आत्मनिर्भरता' की कुंजी भी है।

यूक्रेन जैसे किसी स्वतंत्र देश को अपनी कठपुतली बनाने के रूप से के काम का भावत सैद्धांतिक रूप से समर्थन नहीं कर सकता

चुके हैं। तेल और गैस निर्यात पर प्रतिबंध लगाए बिना पुस्तिको चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन प्रतिबंध लगाने से पहली चोट अमेरिका और यूरोप को लगेगी। यूरोप के देश अब रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने देश में सौ नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इसके लिए पीपीपी यानी निझी-सरकारी भागीदारी माडल के तहत सरकार ने इस साल 22 जनवरी तक राज्य सरकारों, ट्रस्टों एवं एनजीओ से आवेदन आमंत्रित किए थे। देश भर से मात्र 230 आवेदन इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुए। ध्यान देने वाला पक्ष यह है कि 13 प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की है। सवाल यह है कि नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना पर देश में इतनी कमज़ोर प्रतिक्रिया क्यों दर्ज की गई है? केंद्र सरकार खुद अपने संसाधनों से देश के हर जिले में सैनिक स्कूल क्यों नहीं खोल सकती है? भले ही यह कार्य चरणबद्ध तरीके से ही किया जाए। पीपीपी मोड का विकल्प भी बेहतर है, लेकिन यह उतना व्यावहारिक नहीं है।

जीवन में देशभक्ति को अनिवार्यता के धरातल पर नहीं कसा गया। इसीलिए कहीं कहीं तो सुरक्षाबलों और सेना पर लोग खुलेआम पथराव को अपना अधिकार मानने लगे हैं। मौजूदा राजनीतिक वातावरण में भी केवल नागरिक अधिकारों एवं तुष्टीकरण की ही बातें हो रही हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51-ए (डी) कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र सेवा और रक्षा के लिए तप्तर रहे। सगाल यह कि क्या हम राष्ट्र रक्षा के लिए सक्षम नागरिक निर्माण की पर्याप्त व्यवस्था पिछले 75 वर्षों में विकसित कर पाए हैं? दुनिया के करीब 80 देशों के स्कूली पाठ्यक्रमों में सैनिक शिक्षा के अलग-अलग प्रतिधान हैं। इजरायल जैसे देशों में तो अनिवार्य सैनिक शिक्षा की व्यवस्था है, जबकि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में महज पांच मिलियन स्कूल और 33 सैनिक स्कूल ही संचालित हैं। इन स्कूलों में केवल तीन हजार बच्चों को प्रवेश मिलता है। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष केवल 60.51 करोड़ रुपये की राशि ही इन स्कूलों के लिए आवंटित की थी। पांच मिलियन स्कूलों के लिए तो यह राशि महज 6.17 करोड़ रुपये ही थी। जबकि अलीगढ़ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को लेकर

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत को आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। देश की संपत्ति की सुरक्षा तक के लिए सरकारों को सार्वजनिक अपील करनी पड़ती है। जिस तरह से राष्ट्र दशकों से आतंकवाद के दंश को भोग रहा है वह हमारे नागरिकों की संलिप्तता के बिना संभव नहीं है। संविधान सभा के सदस्य डा. हृदयनाथ कुंजरू ने 1959 में सैनिक शिक्षा को देश में अनिवार्य करने की वकालत की थी ताकि भारतीय युवा न केवल स्वस्थ हों, बल्कि वे देशसेवा के लिए सदैव मानसिक रूप से तैयार रहें। दुर्भाग्य यह कि स्वतंत्रता के बाद नागरिकों में देशभक्ति और अनुशासन सिखाने के मामले में सरकारें भी पूरी तरह से उदासीन रहीं। असल में संवैधानिक रूप से ही नागरिक सरकार से 1001 करोड़ रुपये और जेनर्न्यू को करीब 380 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इन दो नों विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ होता रहता है, यह किसी से छिपा नहीं। सैनिक और मिलिट्री स्कूलों से निकलने वाले छात्र न केवल सेना में सेवा को प्राथमिकता देते हैं, बल्कि अन्य मोर्चों पर भी अपनी प्रभावोत्तमाद के जवाबदेही की छाप छोड़ते हैं। सैनिक स्कूल से निकलने वाले अधिकतर छात्र सेना को अपने करियर के तौर पर प्राथमिकता देते हैं। सैनिक स्कूल को सेना का प्रवेश द्वारा भी कहा जाता है। सैनिक स्कूलों ने सशस्त्र सेनाओं में अब तक 7000 से अधिक अधिकारियों की भर्ती में अपना योगदान दिया है। एक यह तथ्य भी है कि आज सेना में काबिल अफसरों की बड़ी कमी है। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़े? से इस मुख्य स्तंभ बन चुका है। यूरोप और अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार हैं। लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के मामले में भी रूस की अपेक्षा यूरोप-अमेरिका भारत के अधिक निकट है, पर अब रूस और अमेरिका-यूरोप आमने-सामने हैं और दोनों भारत से समर्थन की उम्मीद रखते हैं। 2014 में क्रीमिया को हड्डपने के मामले में भारत ने यह कहा हुए पलु ज्ञाइ लिया था कि क्रीमिया के साथ 'रूस के वज़िब हित' जुड़े हैं। अमेरिका-यूरोप ने भारत की इस टिप्पणी को पचा लिया और पुतिन ने इसे अपना समर्थन मानकर भारत का ध्यान्यवाद किया, लैकिन यूक्रेन जैसे किसी स्वतंत्र देश के राजनीतिक-सैनिक तंत्र को धस्त कर अपनी कठपुतली बनाने के काम का भारत सैद्धांतिक रूप से समर्थन नहीं कर सकता।

मणिपुर विधानसभा चुनाव में नदी संरक्षण का मसला

एक जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज यानी केवल एक बात उपयोग में आने वाले प्रूफिस्टिक के उपयोग पर पाबंदी के नए आदेश से मणिपुर की राजधानी फ़िफाला की एक नदी की जान में जान आव



समय हर राजनीतिक दल बेशुमार कचरे के कारण मौत के कगार पर खड़ी इंफाल की एक नदी के संरक्षण का मसला जरूर उठाते हैं, लेकिन जमीन पर कभी कुछ होता दिखा नहीं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में 'मा' का बाजार दुनिया में एक अनूठा व्यावसायिक स्थल है जहां केवल महिलाएं ही दुकानें चलाती हैं। सदियों पुराने इस बाजार में लगभग पांच हजार महिलाओं का व्यवसाय है। बीते दो दशकों के दौरान जिस वस्तु ने खरीदारी करने वालों को सामान ले जाने के लिए सुविधा दी, वही आज इस बाजार और इससे सटी नांबुल नदी के अस्तित्व पर संकट का कारण बन रही है। इस बाजार में आने वाली फल-सब्जी का उत्पादन इस नदी के जल से होता है। नदी के जल की सहज धारा कभी यहां के भी यह देश की सबसे दूषित नदियों में शामिल है। विदित हो कि सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच अलग-अलग प्राथमिकता के आधार पर देश की 351 नदियों को अत्यधिक प्रदूषित के रूप में पहचाना था, जिसमें मणिपुर की नींनदियों को सूचीबद्ध किया गया था, उनमें नांबुल एक है। अकेले इंफाल से हर दिन लगभग 12 टन कूड़ा निकलता है और इसके निबटारे की कोई माकूल व्यवस्था है नहीं। या तो इस कूड़े को शहर के बाहर पहाड़ी क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है या फिर शहर के बीच से गुजरती नांबुल नदी में डाल दिया जाता है। लगातार कूड़ा फेंकने से जब शहर में नदी ढक गई तो स्थानीय प्रशासन ने 2018 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शहर में 50 माइक्रान से शपवान से पता चला कि इकात शहर में साल दर साल सांस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और इसके मूल में भी प्रूसिक कचरा ही है। यह बात अब सबको खटक रही है कि इंफाल में पेयजल के मुख्य स्रोत नांबुल नदी 10 किमी के अपने रास्ते में नदी के रूप में दिखना ही बंद हो गई है। केवल यह नदी ही नहीं, इसके अलावा राज्य की अन्य आठ नदियों की भी कमोडेश यहीं दशा है। यानी आज मणिपुर की नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और जागरूक लोग इसे मतदान के दबाव से बचाने का प्रयास कर देश के सामने सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे एक बड़ा विरमश्य यह भी खड़ा हो सकता है कि मणिपुर के लोग जल संरक्षण के मसले को प्राथमिकता देते हैं, जैसाकि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कम ही दिखता है।

